



अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए इंदौर को प्राथमिकता

5 हजार करोड़ रुपए
के बांड जारी करेगा
एअरपोर्ट प्राधिकरण

भास्कर संवाददाता. इंदौर

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए इंदौर व भोपाल दोनों शहर दावेदारी कर रहे हैं। एअर ट्रैफिक के हिसाब से तय किया जाएगा कि पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ान किसे मिलेगी। आर्थिक मंदी से बचने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण 5 हजार करोड़ रुपए के बांड जारी करेगा।

यह बात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन वी.पी. अग्रवाल ने कही। वे यहां देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर नई टर्मिनल बिल्डिंग व रन-वे क्षेत्र का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने कहा नई टर्मिनल बिल्डिंग फरवरी 2010 तक ही बन पाएगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ान की मांग कर रहे इंदौर व भोपाल के बारे में उन्होंने कहा वैसे प्रदेश की राजधानी को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। यहां ट्रैफिक भी अच्छा



एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन वी.पी. अग्रवाल के साथ डायरेक्टर विवेक उपाध्याय।

है। हो सकता है दोनों शहरों को अंतरराष्ट्रीय उड़ान मिले। टर्मिनल बिल्डिंग में पार्किंग बनाए जाने की समस्या पर राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। जगह नहीं मिलती है तो 50 मीटर की दूरी पर पार्किंग बनाई जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा अब यहां कार्गो सेवा की संभावना भी बढ़ गई है। शहर में एसईजेड सहित कई कंपनियां हैं। प्रदेश में एअरपोर्ट पर 850 करोड़ खर्च कर रहे : एअरपोर्ट अथॉरिटी इंदौर को इंटरनेशनल एअरपोर्ट बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर, इंदौर सहित अन्य विमानतलों पर साढ़े

नई कार्गो सेवाएं शुरू
हो सकती हैं

रन-वे की लंबाई बढ़ने से इसमें 5 डी श्रेणी के विमान एवं एक बड़ा एअरक्राफ्ट आ सकता है। नई एअरलाइंस कंपनियां भी कार्गो सेवा शुरू कर सकती हैं। एअरपोर्ट पर आए दिन होने वाली पक्षियों के टकराने की बात पर उन्होंने कहा यहां हूटर या जोन गन लगाएंगे। मौसम की खराबी से हवाई यातायात प्रभावित होने की बात पर उन्होंने एयरपोर्ट डायरेक्टर विवेक उपाध्याय से पूछा। उन्होंने कहा इंदौर में यह समस्या नहीं आती है। यहां रडार लगाए जाने की आवश्यकता भी नहीं है।

आठ सौ रुपए खर्च कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देशभर में साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एअरपोर्ट के निजीकरण के बारे में श्री अग्रवाल ने कहा कि एअरपोर्ट पर खर्च ज्यादा आने की वजह से विमानतलों का निजीकरण करना पड़ रहा है।